an>

Title: Need to provide electricity in all Government primary schools.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। यह योजना पूर्ण रूप से सम्पन्न हो इस हेतु विद्यालयों में मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया जाता है। बच्चों को पुस्तकें, ड्रेस तथा पढ़ाई के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। भवन, शिक्षक, स्वच्छता आदि की समस्याएं तो हैं हीं लेकिन अधिकांश विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण इन विद्यालयों की बिजली काट दी गई है। केवल अपने संसदीय क्षेत्र मेरठ की यदि मैं बात करूं तो मेरठ में कुल 910 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें से 255 विद्यालयों में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तथा बचे हुए 655 विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में बिजली के बिलों का भुगतान न होने की वजह से प्रशासन द्वारा बिजली काट दी गई है। पिछले सप्ताह जी-टीवी ने विद्यालयों की स्थिति पर बहुत विस्तार से उल्लेख किया था। इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का बिजली बिलों का भुगतान न होने में कोई दोÂष नहीं है फिर भी इसके दुÂष्परिणाम भीषण गर्मी के रूप में उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिजली बिलों के भुगतान के अभाव में काटे गए कनेक्शनों को यथाशीघ्र पुनर्स्थापित किया जाए तथा प्राथमिक विद्यालयों द्वारा बिजली बिलों के भुगतान में असमर्थता के कारणों का पता लगाकर व्याप्त खामियों के निदान हेतु तुरंत सुधारात्मक क़दम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चंदेल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।